

दैनिक



भोपाल की धड़कन

साध्य प्रकाश

संस्थापक- स्व. सुरेंद्र पटेल



बालासोर रेल हादसा

288 की मौत

पीएम मोदी ने विशेष बैठक बुलाई, घटनास्थल जाएंगे

ओडिशा में राजकीय शोक, रेलमंत्री वैष्णव और ओडिशा के सीएम पटनायक पहुंचे मौके पर, भाजपा ने देश भर में कार्यक्रम रद्द किए



मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर विमानतल पर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड को मध्यप्रदेश की सकुशल यात्रा के पश्चात विदाई दी।

सांध्यप्रकाश विशेष

23 आईएस सचिव स्तर के पदों के लिए इम्पेनल्ड

मप्र के 3 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के 23 आईएस अधिकारियों को सेक्रेटरी या उसके समान स्तर के पदों पर एपैन्लड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। ये अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990,91 और 92 बैच के अधिकारी हैं।

इन अधिकारियों में मध्यप्रदेश के तीन अधिकारी शामिल हैं। ये है नीलम शमी राव, पंकज अग्रवाल और वीपल कांता राव। यह तीनों अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1992 बैच के अधिकारी हैं।

देश के अन्य आईएस अधिकारियों में विभु नायर,पुनीत कुमार, अरुणिश चावला, चंचल कुमार, निधि खरे, विनीत जोशी, विमलुनमंग व्यालनाम, रजत कुमार मिश्रा, संजय जाजू, जे राधाकृष्णन, नीरज मित्तल,नरेंद्र भूषण, सुभाष चंद्र लाल दास, प्रदीप कुमार मोहपात्रा, आशीष कुमार भट्टानी, राकेश रंजन, राजेंद्र कुमार, शशि रंजन कुमार, श्रीराम तरानीकांत और विजय कुमार शामिल हैं।

Jagat Prakash Nadda

@JPNadda

...

ओडिशा के बालासोर में कल शुक्रवार शाम को हुआ भयावह रेल हादसा अत्यंत ही दुःखद और मन को शोकाकुल कर देने वाला है। मैं इस हृदय विदारक घटना से मर्माहत हूँ।

इस भीषण रेल दुर्घटना को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों के साथ-साथ देश भर में होने वाले अपने सारे कार्यक्रमों को आज के लिए स्थगित कर दिया है।

मैं परमपिता परमेश्वर से शोक संतप्त परिवारों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। ईश्वर मृत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे।

ॐ शान्ति।

Translate Tweet

7:05 AM · 03/06/23 from Earth · 5,382 Views

72 Retweets 2 Quotes 277 Likes

मुंबई पुलिस के हाथ लगी ड्रग्स की भारी खेप, 4860 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत

मुंबई। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2400 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग्स नष्ट किया है, जिसकी कीमत 4860 करोड़ रुपए बताई जा रही है।

नई दिल्ली। ओडिशा में शुक्रवार शाम हुए भीषण रेल हादसे में मृतकों का आंकड़ा 288 हो गया है। वहीं 850 के करीब लोग घायल हैं। इस घटना के महेनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओडिशा जाएंगे। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और हालात का जायजा लिया था। हादसे की गंभीरता को देखते हुए युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं और सेना को भी बचाव कार्यों में लगा दिया गया है। हादसे को लेकर पीएम मोदी ने बैठक भी बुलाई है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पहले शालीमार-चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिलेड हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलट गए। दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर-हावड़ा एक्सप्रेस इनसे टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेन की कुछ बोगियां पटरी से उतर गईं। ये बोगियां दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा भिड़ी। कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन और कुछ बोगियां मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गईं। अधिकारियों ने बताया कि ओडिशा के बहनगाबाजार में हावड़ा से बंगलुरु जा रही 12864 एक्सप्रेस के कई कोच शुक्रवार शाम करीब 7 बजे पटरी से उतरकर साथ वाले ट्रैक पर जा गिरे। इसी दौरान, उस ट्रैक पर 12841 शालीमार-चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और पलटो डिब्बों से टकरा गई। इससे कोरोमंडल के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और बागल के ट्रैक से गुजर रही मालगाड़ी से टकरा गए। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने यात्रियों को निकालना शुरू किया। बाद में एनडीआरएफ, राज्य सरकार और वायुसेना ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। हादसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस के सात कोच पलट गए, चार कोच रेल बाउंड्री के बाहर चले गए। स्थानीय लोगों के अनुसार, कुल 15 डिब्बे पटरी से उतरे।

रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए

विपक्ष के नेताओं ने हादसे के लिए जिम्मेदार सिग्नल फेल्योर के लिए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकापा) के नेता अजित पवार ने कहा कि जब पहले इस तरह की दुर्घटनाएं होती थीं तो रेल मंत्री इस्तीफा दे देते थे। पवार ने कहा, लेकिन इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। भाकपा नेता बिनय विश्वाम ने कहा कि सरकार का ध्यान केवल लक्जरी ट्रेनों पर है जबकि आम लोगों के लिए ट्रेनें और पटरियां उपेक्षित हैं। बिनाय विश्वाम ने ट्वीट किया, सरकार केवल लक्जरी ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करती है। आम लोगों की ट्रेनें और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। उड़ीसा में हुई मौतें इसी का परिणाम हैं। रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

गुणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि सिग्नल फेल होने से इतना बड़ा हादसा विश्वास से परे और आश्चर्यजनक है। हादसे ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब दिया जाना चाहिए। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि तीनों ट्रेनें एक-दूसरे पर कैसे ढेर हो गईं। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि डाउन लाइन पर बंगलुरु-हावड़ा ट्रेन शाम 6.55 बजे पटरी से उतर गई और कोरोमंडल शाम 7 बजे अप लाइन पर पटरी से उतर गई। कोरोमंडल के पटरी से उतर डिब्बे पहले बंगलुरु-हावड़ा और फिर मालगाड़ी से टकरा गए।

घायलों की मदद के लिए 2000 से अधिक लोग अस्पताल पहुंचे

घायलों की मदद के लिए बालासोर मेंडकल कॉलेज और अस्पताल में रात में 2,000 से अधिक लोग इकट्ठा हुए और कई ने रक्तदान भी किया। मुख्य सचिव जेना ने जरूरत की घड़ी में दुर्घटना पीड़ितों को रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बालासोर में रात भर मैं पांच सौ यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वर्तमान में स्टॉक में नौ सौ इकाइयां हैं। इससे दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में मदद मिलेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी स्वयंसेवकों का ऋणी और आभारी हूँ जिन्होंने एक नेक काम के लिए रक्तदान किया है। रक्तदान करने आए एक व्यक्ति ने कहा, लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है, कई लोग ऐसे हैं जिनके घर-हाथ नहीं हैं। मैंने रक्तदान कर दिया जिससे किसी की जान बच सके और वे अपने घर जा सकें।

कवच होता तो टल सकती थी ओडिशा ट्रेन त्रासदी

रेलवे प्रवक्ता अमिताभ शर्मा के मुताबिक, इस रूट पर कवच उपलब्ध नहीं था। दरअसल, भारतीय रेलवे ने चलती हुई ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कवच नामक एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली ट्रेन ड्राइवरों को एक विश्वसनीय साथी है। यदि ड्राइवर कहीं स्पीड कंट्रोल करना या ब्रेक लगाना भूल जाता है तो कवच प्रणाली ब्रेक इंटरफेस यूनिट द्वारा ट्रेन को कंट्रोल कर लेती है।

कवच सिस्टम भी जुमला निकला?

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि जब इंजन में रेल मंत्री सवार रहता है तो दो ट्रेनें एक दूसरे से 380 मीटर दूर ही रुक जाती है। वीडियो बना के वाहवाही लूटाना तो ठीक है पर अब दुर्घटना की जवाबदारी लेने के वकूत किसी को बिल का बकरा बनाया जाएगा। एक अन्य यूजर ने लिखा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कवच सिस्टम भी जुमला निकला? एक यूजर ने लिखा कि कुछ महीने पहले ट्रेन की टक्कर रोकने के लिए बनाए गए कवच सिस्टम के लिए रेल मंत्री छाती ठोक रहे थे।

रेल सुरक्षा के नाम पर लाखों खर्च

सोशल मीडिया पर अन्य एक यूजर ने रेल सुरक्षा के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च पर सवाल उठाए। यूजर ने लिखा कि ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच के नाम पर 50 लाख प्रतिकिलोमीटर खर्च किए गए। इसके बावजूद लेकिन अभी भी लोग मर रहे हैं। यूजर ने सवाल उठाया कि आखिर टैक्सपेयर्स के पैसे का क्या हो रहा है। सेफ्टी अपग्रेड के नाम 34 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

रेल मंत्री का कवच सिस्टम बनाम बालासोर का खौफनाक मंजर

बालासोर का खौफनाक मंजर। अंधेरे में अपनों को तलाशते दहशतजदा लोग। बिखरे शव। सैकड़ों जिंदा लोग, किसी का हाथ कट गया है तो किसी का पांव। कोई जानवर से भी टकराकर टूट जाती है। और हरी झंडी दिखाव रहे हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन रेलवे के उस कवच का क्या हुआ, जिसकी बड़ी पब्लिसिटी की जा रही थी। किराया से लेकर सब कुछ बढ़ा दिया, रेलवे बेचने तक की तैयारी है, लेकिन रेल दुर्घटनाएं रोकने की ठोस बात नहीं हो रही। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना ने रेलवे के तमाम दावों की बखिया उधेड़ दी है। सारे सिस्टम की पोल खुल गई है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एकदम नाकारा ही साबित हो रहे हैं।

रेलवे स्टेशन निजी हाथों में दे दो। ट्रेन भी निजी हाथों में दे दो। फिलहाल, हम नई-नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करवा रहे हैं, जो एक जानवर से भी टकराकर टूट जाती है। और हरी झंडी दिखाव रहे हैं प्रधानमंत्री से। लेकिन रेलवे के उस कवच का क्या हुआ, जिसकी बड़ी पब्लिसिटी की जा रही थी। किराया से लेकर सब कुछ बढ़ा दिया, रेलवे बेचने तक की तैयारी है, लेकिन रेल दुर्घटनाएं रोकने की ठोस बात नहीं हो रही। ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना ने रेलवे के तमाम दावों की बखिया उधेड़ दी है। सारे सिस्टम की पोल खुल गई है। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एकदम नाकारा ही साबित हो रहे हैं।

और रेल मंत्री का कवच सिस्टम, वो भी जुमला निकला? रेलवे प्रवक्ता कहते हैं, इस रूट पर कवच उपलब्ध नहीं था। दरअसल, भारतीय रेलवे ने चलती हुई ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कवच नामक एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी) प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली ट्रेन ड्राइवरों की एक विश्वसनीय साथी है। यदि ड्राइवर कहीं स्पीड कंट्रोल करना या ब्रेक लगाना भूल जाता है तो कवच प्रणाली ब्रेक इंटरफेस यूनिट द्वारा ट्रेन को कंट्रोल कर लेती है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? एक या कुछ रेल अधिकारी? फिर, मंत्रालय क्या घास खोदने के लिए बनाया गया है? क्या रेल मंत्री और दिल्ली में बैठे उनके अफसर केवल मुफ्त की तनखाह लेने और ऐश करने के लिए बने हैं?

कुछ महीने पहले ट्रेन की टक्कर रोकने के लिए बनाए गए कवच सिस्टम के लिए रेल मंत्री छाती ठोक रहे थे, अब ये क्या हुआ हर किसी को यह पूछना चाहिए। जब एक ट्रेन डिले होकर दूसरे ट्रैक पर आ गयी थी, तब कवच कहीं था? 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इन दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा? एक नहीं, दो नहीं, 3-3 ट्रेनें आपस में टकराईं, तब भारत का कवच कहाँ था? सिग्नल फेल होने से इतना बड़ा हादसा विश्वास से परे और आश्चर्यजनक है। हादसे ने कुछ गंभीर सवाल खड़े किए हैं जिसका जवाब आना चाहिए। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि तीनों ट्रेनें एक-दूसरे पर कैसे चढ़ गईं। शुरुआती खबरों में कहा गया है कि डाउन लाइन पर बंगलुरु-हावड़ा ट्रेन शाम 6.55 बजे पटरी से उतर गई और कोरोमंडल शाम 7 बजे अप लाइन पर पटरी से उतर गई। कोरोमंडल के पटरी से उतर डिब्बे पहले बंगलुरु-हावड़ा और फिर मालगाड़ी से टकरा गए। सरकार का ध्यान केवल लक्जरी ट्रेनों पर है जबकि आम लोगों के लिए ट्रेनें और पटरियां उपेक्षित हैं। उड़ीसा में हुई मौतें इसी का परिणाम हैं। रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए।

रेल सुरक्षा के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च पर भी सवाल उठाना लाजिमी है। सोशल मीडिया पर लिखा गया है कि ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच के नाम पर 50 लाख

प्रतिकिलोमीटर खर्च किए गए। इसके बावजूद लेकिन अभी भी लोग मर रहे हैं। आखिर टैक्सपेयर्स के पैसे का क्या हो रहा है? टैक्सपेयर्स तो ठीक, जो लोग किराया देकर रेलों में यात्रा कर रहे हैं, उनके पैसे काहे में जा रहे हैं? कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन में? सेफ्टी अपग्रेड के नाम 34 हजार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। काहे में खर्च हुए? क्या हम दुर्घटना में मृत लोगों की जिंदगी वापस दे सकते हैं? अपंग होने वालों के अंग वापस दे सकते हैं? संवेदनाओं के नाम पर बयानबाजी..और बयानबाजी..। तर्क-कुतर्क..। और फिर सब कुछ सामान्य। चलाओ दुरंतो। चलाओ वंदे भारत। और करते रहो हजारों लोगों को शहीद।

और अंत में..

संदर्भ के अनुसार देश के पूर्व रेल मंत्री रहे सर्वश्री लालबहादुर शास्त्री, जगजीवन राम, कमलापति त्रिपाठी एवं माधवराव सिंधिया ने रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। अब देखा है वर्तमान रेल मंत्री का इस्तीफा कब होता है? और होता भी है या नहीं?

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆

रोटरी क्लब ने तत्काल मरीज को दिलाई मशीन

भोपाल। रोटरीयन अनिल कुमार गुप्ता रोटरी क्लब भोपाल हिल्स के सक्रिय सदस्य हैं। एक मरीज को कन्सन्टेटर मशीन की आवश्यकता थी। अजीत सिंह उबेजा ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सुबह 9:31 बजे मरीज तक कन्सन्टेटर मशीन इमरजेंसी में पहुंचाने का अनुरोध किया। रोटे अनिल कुमार गुप्ता जो समूचे भारत के विभिन्न स्वास्थ्य सेवी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उन्होंने अपने स्वास्थ्य सेवा पर आधारित शक्तिशाली नेटवर्क पर काम शुरू कर दिया। सुबह 11:38 पर मशीन शीकू तक पहुंच गई, इस 2 घंटे 7 मिनट में काम हो गया। रोटरी अजीत सिंह उबेजा ने राहत की सांस लेते हुए न केवल मरीज की सहायता की बल्कि अपेक्षाकृत कम समय में मशीन को उपलब्ध कराने पर रोटरीयन अनिल कुमार गुप्ता को हार्दिक धन्यवाद दिया। यह मानवसेवा रोटरी क्लब भोपाल हिल्स के कर्मठ, सक्रिय कार्यकर्ता रोटे अनिल कुमार गुप्ता ने कर दिखाया। रोटे कर्नल डी सी वर्मा , क्लब प्रशिक्षक ने बताया कि रोटरीयन अनिल कुमार गुप्ता ने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और परेशानियों से निजात दिलाने में महारत हासिल की है।

एलएनसिटी में युवा उद्यमी सम्मेलन आज

भोपाल। शहर के रायसेन रोड स्थित एलएनसीटी कॉलेज मे युवा उद्यमिता सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह सम्मेलन 3 जून को कॉलेज परिसर में सुबह 10 बजे से प्रारम्भ होगा, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। इस सम्मेलन मे भोपाल शहर के 10 से अधिक युवा उद्यमि आ रहे हैं, जो अपनी सफलता कि कहनी युवाओं से साझा करेंगे। इनमे कुल्लडवाला के संस्थापक लक्ष्य मीना, शाही दाबार के संस्थापक आकाश वीरानी, नेस्टऑफिक्स के अभय गुप्ता, वमोस इलेक्ट्रिक के आर्यन्स व्यास और मानसी माथुर, श्री धननारायण प्राइवेट लिमिटेड के अमर शर्मा आदि शामिल है। समनेलन मे युवाओं को इन सफल उद्यमियों से सीधा संवाद करने का अवसर मिलेगा। सम्मेलन में लकी ड्रा भी निकाला जायेगा, जिसमें विजेता को 20 हजार रुपये का पुस्कार प्रदान किया जाएगा। सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी युवाओं को पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीकरण शुल्क 200 रुपये निर्धारित है।

इंपीरियल हायर सेकेंडरी स्कूल छावनी का परीक्षा परिणाम अत्वल

भोपाल। 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में इंपीरियल सेकेंडरी स्कूल बेहतरान प्रदर्शन किया है यहां 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में ज्यादातर छात्रों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इंपीरियल हाई सेकेंडरी स्कूल के संचालक यासीन अहमद खान ने बताया कि विगत 2 साल कोरोना के बाद छात्रों के अध्ययन के लिए टीचर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी और 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम में अध्यापकों द्वारा की गई इस मेहनत का बेहतर प्रतिसाद मिला है दसवीं की परीक्षा में 56 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी एवं 12वीं की परीक्षा में 28 विद्यार्थियों में द्वितीय श्रेणी प्रथम श्रेणी मेरे पास की है 12वीं में उच्चतम अंक 84.9 प्रतिशत रहे।

सूरज प्रीमियम हाई सेकेंडरी स्कूल का बेहतर प्रदर्शन

भोपाल। सूरज प्रीमियम हाई सेकेंडरी स्कूल में दसवीं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम में बेहतर प्रदर्शन किया है सूरज प्रीमियम हायर सेकेंडरी स्कूल के संचालक अजय साहू ने बताया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 70 बच्चों ने प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास की है जबकि 12वीं की परीक्षा में 45 छात्रों ने प्रथम श्रेणी हासिल की है एवं उच्चतम अंक 94 प्रतिशत हासिल किए हैं। अजय साहू बताते हैं कि उनके स्कूल पर शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है यह शहर के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक है जिसे आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त है अजय साहू ने कहा कि शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के चलते ही उनके द्वारा जुनियर सेक्शन और हायर सेकेंडरी सेक्शन को अलग-अलग भवनों से संचालित किया जाता है सूरज प्रीमियर हर सेकेंडरी स्कूल में लगभग 1600 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

कम्प्युनिकेटिंग विथ कॉन्फिडेंस विषय पर कार्यशाला का आयोजन

संत हिरदाराम नगर। संत हिरदाराम कन्या महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा कम्प्युनिकेटिंग विथ कॉन्फिडेंस विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं को आवश्यक संचार कौशल से अवगत कराना था। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. डालिमा पारवानी ने कहा कि छात्राओं को व्यवहारिक प्रायोगिक ज्ञान होना आवश्यक है। अकादमिक और इंडस्ट्री के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करने के लिए यह कार्यशालाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विषय विशेषज्ञ डॉ. यशी तिवारी ने विभिन्न जीवंत उदाहरणों द्वारा प्रभावी संगठनात्मक संचार, संचार का महत्व, अनुभूति एवं दृष्टिकोण इत्यादि को विस्तार प्रभावी ढंग से बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में संचार कौशल की जानकारी होना आवश्यक है। इस कार्यशाला में भोपाल के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्यालयों की छात्राओं ने भाग लिया।

थिंक गैस ने बैरागढ़ में सीएनजी स्टेशन खोला

भोपाल। थिंक गैस ने भोपाल के बैरागढ़ में अपना कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीएनजी) स्टेशन लांच कर दिया है। इस नए स्टेशन के खुलने के साथ भोपाल में थिंक गैस का नेटवर्क बढ़कर 26 सीएनजी स्टेशनों पर पहुंच गया है जिससे इस क्षेत्र में लोगों को पर्यावरण अनुकूल एवं सुगम ईंधन विकल्प उपलब्ध कराने की इस कंपनी की दृढ़ प्रतिबद्धता का पता चलता है।

भोपाल-इंदौर राज्य राजमार्ग 28 पर स्थित यह नया सीएनजी स्टेशन, भोपाल में संत हिरदाराम नगर और कॉमर्शियल बस डिपो के पास एक प्रमुख स्थान पर है। इस आदर्श स्थान की वजह से इस क्षेत्र के निवासियों और कारोबारियों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा और इस संस्थागत केंद्र की अधिक यातायात की मांग पूर्ति सुनिश्चित होगी। इस इलाके में संत हिरदाराम कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉलेज, स्कूल, चिरायु मेडिकल कॉलेज



एंड हॉस्पिटल और विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज और स्कूल मौजूद हैं। थिंक गैस बैरागढ़ स्टेशन ओटी, एससीवी, एलसीवी, वाणिज्यिक वाहनों और स्कूल बसों के लिए एक ही जगह पर सभी समाधान उपलब्ध करानेगा और इन वाहनों की सीएनजी भरणे की जरूरत प्रभावी और सुविधाजनक तरीके से पूरी करेगा। पारंपरिक ईंधनों का एक विश्वसनीय और किफायती विकल्प पेश कर रही थिंक गैस

कलेक्टर और विधायक के साथ सिंधी समाज के प्रतिनिधियों की बैठक 70 साल से लंबित पट्टे, सिंधी समाज की समस्या के निराकरण की बंधी उम्मीद

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

विभाजन के समय पश्चिमी पाकिस्तान (सिंध प्रदेश) से आकर विस्थापित किए गए संत हिरदाराम नगर के सिंधी परिवारों को एक बार फिर पट्टा समस्या के निराकरण की उम्मीद बंधी है। हुजूर के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा की पहली पर शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह, एसडीएम मनोज उपाध्याय, सिंधी सेन्ट्रल पंचायत के अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ईसरानी, महासचिव सुरेश जसवानी, संरक्षक ईश्वरदास हिमथानी, वासुदेव वाधवानी, पून्य सिंधी पंचायत अध्यक्ष साबुमल रौझवानी, महासचिव माधु चांदवानी, उपाध्यक्ष नंदलाल दादलानी, कोषाध्यक्ष गुलाब जेठानी, कपड़ा एसोसियेशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल ईसरानी, समाज सेवी डा. अर्जुनदास मंगतानी, शिक्षाविद एवं साधु वासवानी स्कूल संस्थान के सचिव विष्णु गेहानी, संस्कार संस्था के सचिव बसंत चेलानी, गांधीनगर सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रमेश हिगोरानी, सिंधु समाज के अध्यक्ष मोहनलाल चंदनानी, भाजपा मण्डल अध्यक्ष कमल वीधानी, के अलावा समाज सेवी शंकर मेंधानी, मोहन मीरचंदानी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

1000 फार्म वितरित किए जाएंगे: बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि चूंकि पट्टा प्रदान करने का अन्य कोई उपाय नहीं है इस लिए 31 मार्च 2023 को राजस्व विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के अन्तर्गत सिंधी विस्थापितों के पट्टे प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए एक हजार फार्म शनिवार 3 जून से सिंधी सेन्ट्रल पंचायत एवं पून्य सिंधी पंचायत के माध्यम से संत हिरदाराम नगर के सिंधी परिवारों को घर घर बांटे जाएंगे।

12 जून से लग्गा शिविर: बैठक में यह भी तय किया गया कि एक हजार आवेदन पत्र बांटने के बाद 12 जून सोमवार से साधु वासवानी स्कूल में जिला प्रशासन की तरफ से शिविर का आयोजन किया जाएगा जिसमें सिंधी विस्थापित परिवार जिन्हें



मकान, दुकान एवं प्लाट के पट्टे नहीं हैं, आवश्यक कागजातों के साथ फार्म भरकर शिविर में अधिकारियों के पास जमा करेंगे। अधिकारी इनका परीक्षण कर अगले कदम के रूप में पट्टे तैयार कर वितरित करने का काम करेंगे।

वन ट्री हिल्स भूखण्डधारियों के लिए पृथक फार्म: बैठक में यह भी तय किया गया कि चूंकि वन ट्री हिल्स के 500 भूखण्डधारियों की बनी हुई तीन गृह निर्माण समितियां नव युवक गृह निर्माण समिति, भारतीय सिंधु गृह निर्माण समिति एवं गांधीनगर सुधार गृह निर्माण समिति चूंकि भंग है, इसलिए उनके लिए अलग से फार्म छपवाकर जल्द ही वितरित किए जाएंगे।

जमा करनी होगी राशि: बैठक में एसडीएम मनोज उपाध्याय ने बताया कि नव युवक गृह निर्माण समिति को लगभग 7.50 लाख रूपए 200 सदस्यों के जमा करना है, जिसका लेटर उन्हें दे दिया गया है। लगभग इतनी ही राशि भारतीय सिंधु गृह निर्माण समिति को भी जमा करनी है, जबकि इससे लगभग

आधी राशि गांधीनगर सुधार गृह निर्माण समिति को जमा करनी है। भारतीय सिंधु गृह निर्माण एवं गांधीनगर सुधार गृह निर्माण समिति को भी राशि जाम करने का लेटर जारी किया जा रहा है।

एक व दो प्रतिशत लग्गी प्र-ब्याज राशि: बैठक में विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह भी जानकारी दी कि प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माजीय श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर अब पूर्व में जहां 10 प्रतिशत प्र-ब्याजी राशि वसूल की जा रही थी, उसे घटाकर 2 प्रतिशत एवं जहां पूर्व 5 प्रतिशत प्र-ब्याजी राशि वसूलने का प्रावधान था, उसे घटाकर एक प्रतिशत किया गया है। इसी तरह 20 वर्गमीटर तक के भूखण्ड वर्तमान बाजार मूल्य के 05 प्रतिशत के बराबर प्रब्याज लेकर वार्षिक भू-भाटक लिया जाएगा।

ईसरानी ने कहा हम जमा करेंगे राशि: बैठक के दौरान कपड़ एसोसियेशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल ईसरानी जो कि वन ट्री हिल्स के भूखण्डस्वामी भी हैं, ने घोषणा की कि नव युवक

संत हिरदाराम नगर की बदली तस्वीर, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात

सिंधी सेन्ट्रल पंचायत करेगी विधायक रामेश्वर शर्मा का नागरिक अभिनंदन

संत हिरदाराम नगर। उपनगर की सामाजिक संस्था सिंधी सेन्ट्रल पंचायत ने अरबों के विकास कार्यों से संत हिरदाराम नगर की तस्वीर व तकदीर बदलने वाले हुजूर के भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा का नागरिक अभिनंदन करने का निर्णय लिया है। पंचायत महासचिव सुरेश जसवानी ने बताया कि सालों से उपेक्षित संत हिरदाराम नगर की बीते दो तीन सालों में पूरी तरह से तस्वीर बदलने का प्रयास किया जा रहा है और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के विकास कार्य या तो किए जा रहे हैं, या सम्पन्न हो चुके हैं। इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव के पहले रामेश्वर शर्मा का नागरिक अभिनंदन किया जाएगा।

जसवानी ने बताया कि विधायक रामेश्वर शर्मा के प्रयासों से दिसम्बर 2022 से लेकर जून 2023 तक लगभग 20 करोड़ की लगगत से सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है,



ऐसा आजादी के बाद पहली बार हो रहा है, जब चप्पे चप्पे को पक्का किया जा रहा है। पंचायत पदाधिकारियों ने बताया कि जब

से 1948 से तत्कालीन बैरागढ़ की बसावट शुरू हुई, तब से ओवर ब्रिज की मांग की जा रही थी कई सरकारें आईं लेकिन मांग पूरी नहीं हो सकी लेकिन विधायक रामेश्वर शर्मा के प्रयासों से न केवल 27 करोड़ की लागत से बिना किसी तोड़फोड़ और नुकसान पहुंचाए ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है बल्कि इसी साल पूरा करने का संकल्प भी लिया गया है। इधर, विधायक रामेश्वर शर्मा के प्रयासों से ही राजधानी का सबसे बड़ा एवं आलीशान संत हिरदाराम गुलाब उद्यान भी बनकर तैयार हो गया है जिसका लोकार्पण स्वामी हिरदाराम के अवतरण दिवस 21 सितम्बर को करने का निर्णय लिया गया है यह उपनगर के बाशिंदों के लिए बहुत बड़ी सौगात



है। गुलाब उद्यान में ही स्वामी हिरदाराम जी की पहली प्रतिमा भी स्थापित होगी।

50 लाख का पगड़ी रस्म हाल: जसवानी ने बताया कि तत्कालीन महापौर आलोक शर्मा ने पगड़ी रस्म हाल के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी लेकिन उपयुक्त जगह नहीं मिलने के कारण उसका निर्माण आधे में छूट गया लेकिन इस मांग को विधायक रामेश्वर शर्मा ने पूरा कर समस्त सिंधी समाज का दिल जीत लिया है। लगभग 50 लाख की लागत से बोरवन पार्क में पगड़ी रस्म के साथ योगा हाल की निर्माण प्रगति पर है।

डबल डेकर एलेवेटेड ओवर ब्रिज: सिंधी सेन्ट्रल पंचायत ने बताया कि राजधानी भोपाल ही नहीं मध्यप्रदेश में पहला डबल डेकर एलीवेटेड ओवर ब्रिज भी संत हिरदाराम नगर में बनना प्रस्तावित है जिसके लिए लगभग 270 करोड़ की राशि खर्च किए जाने का निर्णय लिया गया है यह डबल डेकर एलीवेटेड ओवर ब्रिज ग्राम लाउंडखेड़ी से विस्जैन घाट तक लगभग 3 किलो मीटर क्षेत्र में बनेगी जो बहुत बड़ी सौगात होगी।



संत हिरदाराम नगर। देश के जाने माने सुप्रसिद्ध कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की 10 जून से 14 जून तक 5 दिवसीय शिव पुराण कथा पीपुल्स माल के पीछे होने जा रही है। कथा 2 बजे से 5 बजे तक होगी। कथा में अलग-अलग जगहों से लगभग 5 से 7 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है। इस बड़े आयोजन में सिंधी समाज को जल सेवा का दायित्व दिया गया है यह सेवा सिंधी समाज सेवा ट्रस्ट संत हिरदाराम नगर करेगा। सिंधी समाज सेवा ट्रस्ट लगभग 20 वर्षों से समाज के अतिरिक्त अन्य सभी सभाओं एवं धर्मों की सेवा कर रहा है। श्रद्धालुओं को उक्त सेवा की व्यवस्था के लिये एक बैठक हुई जिसमें यह तय किया गया कि जल सेवा के 10 काउन्टर लगाए जायेंगे और प्रत्येक काउन्टर पर 10-10 सेवादारी सेवा के लिये मौजूद रहेंगे। शुद्ध जल के लिये वाटर केन एवं बाटल की व्यवस्था की गई है। बैठक में सिन्धी समाज सेवा के ट्रस्टीगण के अतिरिक्त सभी समाज संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अभिजीत देशमुख ने दिव्यांगों के लिए एआई तकनीक का एक्सेसरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लांच किया

मार्गदर्शन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके विशेषज्ञों की टीम व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने, प्रश्नों का उत्तर देने और सभी उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहज अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध है।

अभूतपूर्व एआई-संचालित सहायक वितरण प्रणाली का शुभारंभ, विकलांग समुदाय को सशक्त बनाने की सतत प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दर्शाता है। इस पहल से अनगिनत विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव को लेकर समुदाय उत्साहित है। हिमग्राही से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार हमें सामान बांटती है लेकिन हमें इतनी गर्मी में वितरण केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते हैं। डॉ. अभिजीत देशमुख के प्रयासों से, हमें अपने घर के आराम में उच्च-गुणवत्ता, सहायक सामान की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्राप्त होगी।

छतरपुर नपा होगी नगर निगम, बनेगा मेडिकल कॉलेज का नया भवन

मुख्यमंत्री, छतरपुर के गौरव दिवस और महिला सम्मेलन में हुए शामिल, दी 790 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महाराज छत्रसाल की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये छतरपुर में उनका विशाल स्मारक बनाया जायेगा। छतरपुर नगरपालिका को नगर निगम बनायेंगे। जिले के विकास में कोई कोर-कसर छोड़ी नहीं जायेगी। उन्होंने कहा कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज के पुराने टेंडर को निरस्त कर नये टेंडर के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही छतरपुर में 300 करोड़ रुपये की लागत से नवीन मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण किया जायेगा। मुख्यमंत्री आज छतरपुर के गौरव दिवस और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने छतरपुर जिले को अनेक सौगातें देते हुए 790 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महाराजा छत्रसाल महान योद्धा और शौर्य के प्रतीक थे। उन्होंने हिन्दू स्वराज को स्थापित किया। ऐसे शूरवीर और महापुरुष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि छतरपुर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जिस



ठेकेदार द्वारा काफी लम्बे समय से प्रारंभ नहीं किया था उसका टेंडर निरस्त कर दिया गया है। अब नये टेंडर के आदेश दिये गये हैं। शीघ्र ही छतरपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि एक समय था जब बेटीयों को बोझ समझा जाता था। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना ने समाज की सोच को बदल कर बेटी को वरदान बना दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिये प्रदेश में अभियान चल रहा है। अनेक योजनाओं से उन्हें आत्म-निर्भरता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। हमने स्थानीय चुनावों में आधी सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की हैं, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ आज पंच, सरपंच, पार्षद

आदि पदों पर विराजमान हैं। बेटीयों और महिलाओं के महत्व को बढ़ाने के लिये मध्यप्रदेश में सामाजिक क्रांति हुई है। महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदने पर पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है। प्रधानमंत्री आवास पति-पत्नी दोनों के नाम से है। भू-अधिकार पट्टे भी पति-पत्नि के नाम से दिये जा रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने गरीब बहनों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये लाड़ली बहना योजना को लागू कर प्रदेश की सवा करोड़ बहनों के खाते में एक-एक हजार रूपये 10 जून से डालने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 8 जून को प्रदेश में विशेष ग्रामसभाएँ होगी, जिसमें पात्र बहनों के नाम बताये जायेंगे। स्वीकृति-पत्र घर पहुँचाया

जाएगा। उन्होंने लाड़ली बहनों से कहा कि वे 9 जून की शाम गाँव में गीत गाये, उनके खाते में पैसा आने वाला है। सभी गाँवों में 10 जून की शाम 5 बजे कार्यक्रम होगा और शाम 6 बजे में स्वयं महिलाओं से वचुंअली चर्चा करूँगा। उसके बाद बहनों के खातों में योजना की राशि अंतरित की जायेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक ग्राम एवं छतरपुर और सागर सहित पूरे बुंदेलखंड के विकास के लिए अनेक योजनाएँ दी हैं। उन्होंने कहा कि सागर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद छतरपुर में महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय बनाया गया है। आज 5 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से भवन का लोकार्पण किया गया है।

अंतरराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 250 से अधिक बाइक बरामद और 25 आरोपी गिरफ्तार

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा-निर्देशन में अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना के मार्गदर्शन में अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जा रहा है और चोरी की गई बाइक बरामद की जा रही हैं। इन चोरों तक पहुंचने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ना केवल तकनीक की मदद ले रही है, बल्कि सघन जांच अभियान चलाकर उन्हें पकड़ रही है। इसी के अंतर्गत राजधानी भोपाल सहित जबलपुर और धार जिले में पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कई बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिनमें अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य भी शामिल हैं। पुलिस ने धार, इन्दौर, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, उज्जैन, जबलपुर, कटनी, हरदा और नरसिंहपुर सहित प्रदेशभर में कार्रवाई करते हुए ऐसे गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है, जो अन्य राज्यों में भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने अलग-अलग गिरोह के 25 से अधिक आरोपियों को पकड़कर उनसे 250 से अधिक बाइक बरामद की हैं।

लाखों रुपये कीमत की मोटरसाइकिलें जप्त: मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा अभियान चलाकर बाइक चोरों की धरपकड़ की जा रही है। जबलपुर जिले के 15 थानों द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान लाखों रुपये कीमत की 125 मोटरसाइकिलें जप्त कर 15 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वहीं धार जिले की पीथमपुर पुलिस ने 50 लाख रुपये कीमत की 81 मोटरसाइकिलें जप्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में व बाग पुलिस ने लगभग 25 लाख रुपये की 40 मोटरसाइकिलें जप्त कर चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपियों ने मध्य प्रदेश के 9



जिलों और गुजरात में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। इसी तरह राजधानी भोपाल में बाइक चोर पर कार्रवाई करते हुए ऐशबाग थाना क्षेत्र से 11 लाख रुपये कीमत की 10 बाइक जप्त कर एक आरोपी को व रातीबड़ से 3 बाइक जप्त कर एक आरोपी को पकड़ा है।

इस तरह हुई आरोपियों की गिरफ्तारी: धार जिले के बाग थाना प्रभारी रणजीत बघेल को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि तीन बाइक चोर मोटरसाइकिल से बाग से टांडा जाने वाले हैं। थाने के समीप टांडा बायपास पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए वाले चार लोग दो मोटरसाइकिलों पर आते दिखे। वाहन के कागजात मांगने पर उन्होंने असमर्थता व्यक्त की। पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उन्होंने बाइक चोरी किए जाने की बात कबूल ली। गिरफ्तार करने के पश्चात उन्होंने अन्य बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देना भी स्वीकार किया और बताया कि चुराई गई बाइक मगरदा में हैं। इसी प्रकार धार जिले के पीथमपुर थाने में 8 मई को शाम करीब 8 बजे आरक्षक दिलीप को मुखबिर ने सूचना दी कि पीथमपुर में सेक्टर 3 में

मोटरसाइकिल चोरों की टोली देखी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी समीर पाटीदार को अवगत कराने पर उन्होंने तुरंत टीम गाँठ कर एमपीआरडीसी रोड, जेबीएम कंपनी, खंडहर के पीछे घेराबंदी की और मुखबिर के बताये हुलिये के आधार पर चार बाइक चोरों को गिरफ्तार किया।

डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर चुराते थे बाइक: जबलपुर में भी बाइक चोरी की शिकायतें मिलने और मुखबिर की सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने सक्रियतापूर्वक कार्रवाई करते हुए सैकड़ों मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए क्राइम ब्रांच जबलपुर व जिले के समस्त पुलिस थानों के द्वारा वाहन चोरों के विरुद्ध लगातार 1 माह तक अभियान चलाया गया। जबलपुर पुलिस ने जबलपुर जिले सहित कटनी, हरदा और नरसिंहपुर जिले से चोरी हुए वाहनों को जप्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में चोरों से बाइक बरामद की गई। पूछताछ के दौरान चोरों ने बताया कि ये आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर खड़े वाहनों को डुप्लीकेट चाबी से खोल कर वाहन चोरी कर लेते थे।

एम्स में फाइब्रोस्कैन् सेवाएं शुरू की

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

हाल ही में अत्याधुनिक फाइब्रोस्कैन मशीन के अधिग्रहण के बाद, एम्स भोपाल गर्व से फाइब्रोस्कैन सेवाओं की शुरुआत की घोषणा करता है। इस उन्नत चिकित्सा उपकरण का उद्घाटन दिनांक 2 जून 2023 को एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक डॉ. अजय सिंह की गरिमामय उपस्थिति में हुआ। यह विकास स्वास्थ्य सेवाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पथर है, क्योंकि एम्स भोपाल इस अत्याधुनिक तकनीक को रखने वाला मध्य प्रदेश का पहला सरकारी संस्थान बन गया है। फाइब्रोस्कैन मशीन, जो अब एम्स भोपाल में काम कर रही है, लीवर की विभिन्न बीमारियों के निदान और उपचार में क्रांति लाने के लिए तैयार है। अल्कोहलिक लिवर डिजीज, वायरल हेपेटाइटिस, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से पीड़ित मरीजों को इस इनोवेटिव



डायग्नोस्टिक टेस्ट से काफी फायदा होगा। फैटी लीवर और फाइब्रोसिस के चरण के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करके, फाइब्रोस्कैन मशीन लीवर बायोप्सी जैसी आक्रामक प्रक्रियाओं के लिए एक गैर-इन्वेसिव और समय-कुशल विकल्प प्रदान करती है। इस नई तकनीक का एक प्रमुख लाभ इसकी लागत-प्रभावशीलता है। जहां निजी अस्पतालों में फाइब्रोस्कैन परीक्षण आमतौर पर लगभग 5000 रु. में होता है, मरीज अब एम्स भोपाल में काफी कम दर पर समान सेवा

का लाभ उठा सकते हैं। यह पहल एम्स भोपाल की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और सस्ती बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। फाइब्रोस्कैन सेवाएं चाहने वाले मरीज किसी भी कार्य दिवस पर एम्स भोपाल में मेडिक्लिन ओपीडी से परामर्श कर सकते हैं। एम्स भोपाल के विशेषज्ञ चिकित्सा पेशेवर उच्चतम स्तर की देखभाल प्रदान करने और बेहतर रोगी परिणामों के लिए सटीक निदान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित हैं।

उद्यमिता में मेहनत से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा: राज्यपाल

उज्जैन में किया राष्ट्रीय उद्यमिता जागरूकता शिविर का शुभारंभ

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि महिलाओं ने उद्यमिता के क्षेत्र में जो मेहनत की है, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। संकल्प और शक्ति हमारी मातृ शक्ति की पहचान है। मातृ शक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश, महिलाओं के विकास के विजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस बार का केंद्रीय बजट भी महिलाओं के अर्थिक विकास के मामले में स्व-सहायता समूह ने उल्लेखनीय कार्य किया है। कई वंचित वर्ग की महिलाओं ने अपने आप को साबित करते हुए न केवल परिवार बल्कि देश की अर्थ-व्यवस्था में योगदान दिया है। स्व-सहायता समूह में जो बेटीयों और बहनें आगे बढ़ रही हैं वे पारिवारिक जिम्मेदारी



का निर्वहन भी कर रही है। केंद्र शासन द्वारा मुद्रा एवं स्टार्टअप योजनाओं से महिलाओं के विकास के नए आयाम खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमिता के लिए यह जागरूकता कार्यक्रम सीखने की प्रक्रिया को और तेज करेगा। इसके पहले राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल और अतिथियों ने दीप जला कर विक्रम कीर्ति मन्दिर उज्जैन में भारतीय उद्यमिता संस्थान एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के एक दिवसीय उद्यमिता जागरूकता शिविर की शुरुआत की। केंद्रीय बाल महिला एवं बाल विकास

राज्य मंत्री श्री मुंजपरा महेंद्रभाई ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। उनके सशक्तिकरण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आज आवश्यकता है ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने की जिससे महिला उद्यमियों को कंफेसिटी बिल्डिंग की जा सके। केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना और प्रधानमंत्री जन-धन खातों ने महिलाओं को सशक्त करने में उल्लेखनीय कार्य किया है।

मप्र सहित चार राज्यों में चुनाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश



भोपाल। नवंबर में चार राज्यों में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि उन अधिकारियों के तबादले किए जाएं, जो गृह जिले में पदस्थ हैं। साथ ही जिन्हें चार वर्ष की अवधि में एक स्थान पर पदस्थ रहते तीन वर्ष हो चुके हैं। इसके दायरे में चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों के अलावा अन्य समकक्ष अधिकारी भी आएंगे। आयोग के वरिष्ठ प्रमुख सचिव नरेंद्र एन बुटेलिया ने शुक्रवार को मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए निर्देश में कहा कि 31 जनवरी 2024 की स्थिति में जिन अधिकारियों को एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए तीन वर्ष हो चुके हैं या गृह जिले में पदस्थ हैं, उन्हें स्थानांतरित किया जाए।

इस दायरे में जिला व उप निर्वाचन पदाधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, राजिस्ट्रीकरण व सहायक

राजिस्ट्रीकरण अधिकारी के साथ अतिरिक्त, संयुक्त व उप कलेक्टर, तहसीलदार, विकासखंड और समकक्ष श्रेणी के अधिकारी आएंगे। इसके अलावा पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, कमांडेंट, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक, उप निरीक्षक, रक्षित निरीक्षक और समकक्ष श्रेणी के अधिकारियों के भी तबादले किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए जिन अधिकारियों को तीन वर्ष हो चुके हैं, उन्हें स्थानांतरित कर पालन प्रतिवेदन 31 जुलाई तक देना होगा। यह प्रतिवेदन मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा आयोग को दिया जाएगा। इसके बाद यदि कोई अधिकारी ऐसा पाया जाता है जिसे तीन साल एक स्थान पर पदस्थ रहते हुए हो गए हैं और उसे नहीं हटाया गया है तो आयोग अपने स्तर से उस पर कार्रवाई करेगा। 15वीं विधानसभा का कार्यकाल छह जनवरी 2024 को पूरा हो रहा है। इसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

स्व. कैलाश नारायण सारंग की जयंती पर मना मातृ-पितृ भक्ति दिवस



सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

भाजपा के संस्थापक सदस्य पूर्व सांसद स्व. कैलाश नारायण सारंग की जयंती को संपूर्ण देश में मातृ-पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। नरेला विधानसभा के सभी 17 वार्ड में मंत्री सारंग के साथ कार्यक्रमों में 35 हजार से अधिक बुजुर्गों के पांव पखारने के साथ ही आरती उतार कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर सभी वृद्धजन भाव-विभोर नजर

आये। सभी ने मंत्री सारंग द्वारा किये गये सम्मान को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी हैशटैग मातृपितृभक्ति दिवस के साथ खासकर युवा पीढ़ी ने अपने माता-पिता के साथ ही आसपास के वृद्धजनों को सम्मानित कर उनके फोटो-वीडियो फेसबुक, ट्विटर समेत विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किये। मंत्री सारंग ने नरेला विधानसभा क्षेत्र के वृद्धजनों का सम्मान किया।

स्वच्छ, सुरक्षित जल उपलब्धता में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य

सांध्य प्रकाश संवाददाता ● भोपाल

पर्याप्त मात्रा के साथ स्वच्छ जल की उपलब्धता जल जीवन मिशन का प्रमुख घटक है। सुरक्षित और स्वच्छ जल की उपलब्धता के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ जल से सुरक्षा (एसजेएसएस) अभियान चलाया गया। अभियान की रिपोर्ट में मध्यप्रदेश को अग्रणी राज्य में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर शुद्ध जल पहुँचाने के संकल्प में मध्यप्रदेश सरकार तेजी से कार्य कर रही है। स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान की उपलब्धि मध्यप्रदेश के विकास

के जन-भागीदारी मॉडल का एक और सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में सरकार एवं नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने इस उपलब्धि पर विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, नागरिकों एवं टैरिस्टिंग प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करने वाली समस्त महिलाओं को बधाई दी है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा देशव्यापी अभियान में 2 अक्टूबर, 2022 से 31 मार्च, 2023 की अवधि में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पानी की गुणवत्ता की निगरानी और निरीक्षण की गतिविधियों का मूल्यांकन किया गया। अभियान का लक्ष्य

जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्राम, जिला एवं राज्य स्तर पर व्यापक जन-भागीदारी और पानी की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है।

अभियान में रासायनिक मापदंडों और जीवाणुतत्व संबंधी मापदंडों (मानसून के बाद) का पता लगाने के लिए सभी गाँवों में पीडब्ल्यूएस स्रोतों का परीक्षण, गाँवों में घरेलू स्तर पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, स्कूलों एवं आँगनवाड़ी केंद्रों में पानी की गुणवत्ता का परीक्षण, दूषित नमूनों के लिए किए गए उपचारात्मक कार्य, ग्रामीण स्तर पर एफटीके/एन2एस किट का उपयोग कर जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए महिलाओं का प्रशिक्षण आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।

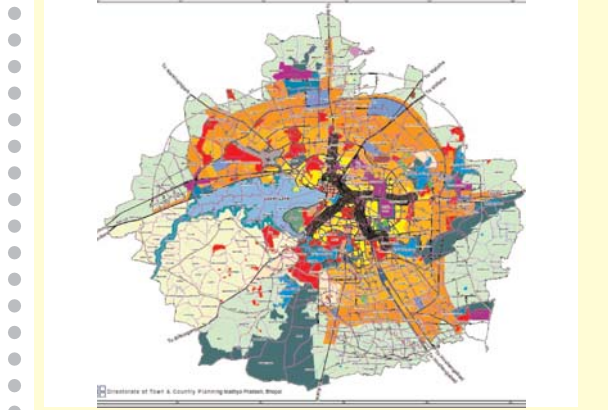
अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, यदि इन्हें हम पीछे छोड़ देंगे तो आर्थिक प्रगति बाधित होगी। आज भारत में स्टार्टअप में महिलाएँ सबसे आगे हैं। यही नहीं 60 प्रतिशत महिलाएँ ऋण लेकर उद्यम चला चला रही हैं। केन्द्र सरकार ने भी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ संचालित कर रखी हैं। आवश्यकता है तो महिलाओं के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की, जहाँ वे अपनी बात रख सकें। साथ ही उनकी मेंटरशिप की भी अत्यधिक आवश्यकता है। संचालक भारतीय उद्यमिता संस्थान श्री सुनील शुक्ला ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, उसमें महिलाओं की भागीदारी स्पष्ट रूप से दिख रही है। उद्यमिता संस्थान 40 वर्षों से लगातार देश में कार्य कर रहा है। महिलाओं में चेतना आई है। इससे वे उद्यमिता में आगे आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमी पैदा नहीं होते बनाये जाते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर उनका संस्थान कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सचिव श्रीमती मीनाक्षी नेगी ने स्वागत भाषण दिया। श्री अमित द्विवेदी ने आभार माना।

सम्पादकीय

अठारह साल बाद मास्टर प्लान

अंततः अठारह साल बाद राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान जारी कर दिया गया। मास्टर प्लान यानि शहर के नियोजन की योजना। कहा तो जा रहा है कि बड़े तालाब, वन क्षेत्र और विशेषकर टाइगर भ्रमण के इलाके को संरक्षित किया जा रहा है, देखना होगा कि इसमें प्रशासन कितना सफल होता है। और शहर के रहसासियों का इसमें कितना सहयोग मिलता है। अभी दावे और आपत्तियों के लिए एक महीने का समय दिया गया है, सो देखना होगा कि दावों–आपत्तियों के बोझ से दबकर कहीं जारी हुआ मास्टर प्लान लागू ही न हो पाए।

भोपाल के मास्टर प्लान–2031 का ड्राफ्ट शुक्रवार को प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है। इसमें वर्ष 2021 में आई आपत्तियों और सुझावों को भी शामिल किया गया है। कलियासोत–केरवा डैम के आसपास के क्षेत्र, जहां टाइगर मूवमेंट और घना वन क्षेत्र है, उस इलाके में निर्माण पर रोक लगी रहेगी। यानी कि इसे ग्रीन बेल्ट के दायरे में रखा गया है। वहीं, 400 हेक्टेयर जमीन भी वन विभाग को दी गई है, ताकि भविष्य में सरकारी भवन भी यहां न बन सके। सतगढ़ी में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का प्रस्ताव है। कुछ इलाकों में सड़कों के चौड़ीकरण आदि को लेकर बीच का रास्ता निकाला गया है, ताकि फिर से उसे लेकर आपत्ति



न आए।

पिछले छह महीने से लगातर मास्टर प्लान को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था। आखिरकार, शुक्रवार को दिनभर चली सुगबुहाइट के बाद ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। दावे–आपत्तियों के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। भोपाल का आखिरी मास्टर प्लान 1995 में जारी किया गया था, जो 2005 में समाप्त हो गया था। इसके बाद से मास्टर प्लान का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, बीच में तीन बार मास्टर प्लान को लेकर कवायदें होती रहीं। 2021 में तो इसे लेकर दावे–आपत्ति भी बुलाए गए थे। हालांकि, इसमें कई बड़े संशोधन किए जाने थे। बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया, टाइगर मूवमेंट एरिया, सड़कों आदि को लेकर यह संशोधन थे। इसके चलते यह ड्राफ्ट जारी नहीं हो सका था।

करीब 12 महत्वपूर्ण संशोधन के साथ प्लान तैयार किया गया है। इसमें बड़ा तालाब के संरक्षण, केरवा डेम के जलभराव क्षेत्र समेत शहर की सड़कों की चौड़ाई पर विशेष फोकस किया गया है। शहर के ग्राम मेंडोरा, मेंडोरी, चिचली, खुशालपुरा, महुआखड़ा, बरखेड़ी, बाज्याफत, रातीबड़, बरखेड़ीखुर्द, भानपुर, केकड़िया, चंदनपुरा, छावनी, खुदागंज, बरखेड़ा नाथू, गौरा में मार्ग को लेकर प्रस्ताव है। इसमें कुछ संशोधन है, क्योंकि कलियासोत–केरवा डैम के पास ग्राम रातापानी से ग्राम मेंडोरा–चंदनपुरा तक वन क्षेत्र फैला है। इस क्षेत्र में बाघों की उपस्थिति होने के कारण यह संवेदनशील क्षेत्र है। बाघों के संरक्षण, वन, ग्रीन बेल्ट आदि को ध्यान में रखते हुए यहां पर निर्माण पर रोक लगाई गई है। यहां की करीब 400 हेक्टेयर जमीन फॉरेस्ट डिपॉर्टमेंट को दे दी गई है। इससे यहां सरकारी बिल्डिंग भी नहीं बन सकेगी। प्राइवेट निर्माण पर भी रोक रहेगी।

लेकिन देखना यह भी होगा कि पहले से संरक्षित क्षेत्रों में जो निर्माण हो चुके हैं, क्या वो सही हैं। वैसे राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में दखल रखने वाले लोगों ने तो बड़े तालाब और छोटे झाड़ू के जंगल वाले क्षेत्रों में भी अनुमतियां ले ली हैं और इस मास्टर प्लान में उन जगहों को भी छोड़ दिया गया है। बनाने वालों के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल भी नहीं आती। जो चाहें, संशोधन कर लें। और वैसे सही बात तो यही है कि इसी कारण तो अठारह बरस से मास्टर प्लान लागू ही नहीं हो पा रहा था। लागू तो ठीक, बन ही नहीं पा रहा था। बनता, फिर संशोधन के लिए रख लिया जाता।

राजधानी और इसके आसपास के इलाकों में सबसे बड़ी समस्या अतिक्रमण की है। और अधिकांश अतिक्रमण प्रभावशाली लोग करते हैं या करवाते हैं। कह सकते हैं कि अधिकांश अतिक्रमण प्रशासनिक, राजनीतिक और कतिपय व्यवसायियों के नेटवर्क के चलते ही हुए हैं और हो रहे हैं। हाल ही में उन स्थानों पर भी निर्माण की अनुमति विशेष लोगों को दी गई है, जहां दूसरे लोगों को अनुमति नहीं दी गई। और तो और, वहां से लोगों को बलपूर्वक हटाया गया। शाहपुरा तालाब के इर्दगिर्द तो कई कालोनियां ही कैचमेंट में बन गईं, प्रभावशाली लोगों के ही कारण। उन्हें न केवल पैसे मिलते हैं, अपितु प्लाट और मकान भी मिल जाते हैं। एक दर्जन से अधिक प्रशासनिक अधिकारियों के आवास बिना अनुमति के ही ताने गए हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं।

खैर..फिलहाल नया मास्टर प्लान आ गया है। उम्मीद है कि तीन महीने के भीतर लागू भी हो जाएगा। शायद इस सरकार के कार्यकाल में ही। कहा जा रहा है कि जल्द लागू भी कुछ लोगों के कारण ही हो रहा है, जिनका बड़ा निवेश है। फिर भी, टाइगर और वन क्षेत्र को सुरक्षित छोड़ने पर ही अमल हो जाए, तो कुछ राहत मिले। और बड़े तालाब सहित तमाम अन्य तालाबों, जल संरचनाओं को यदि जीवनदान मिल जाए तो शायद इस शहर को भी नया जीवन मिल सकता है। कुछ तालाब तो राजनीतिक, प्रशासनिक और बिल्डर माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं, अब भी चेत जाएं।

ब्रह्मदीप अल्टूने

सरकार के प्रति अच्छी राय रखने वाले विचारों को ही केवल अस्तित्व में या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये,क्योंकि गलत राय सरकार और राजशाही दोनों के लिये नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती थी।यह विचार सत्रहवीं सदी में ब्रिटेन मे राजशाही को मजबूत बनाएं रखने के लिए कानून के रूप मे अधिनियमित किया गया था। बाद मे भारत मे भी अंग्रेजों को इसकी जरूरत 1857 की क्रांति के बाद महसूस हुई। 1870 में संभावित विद्रोह के डर से औपनिवेशिक शासकों द्वारा देशद्रोह कानून को भारतीय दंड संहिता या आईपीसी में शामिल किया गया था।

आजादी के आंदोलन मे इस कानून का अंग्रेजों के खूब दुरुपयोग किया। सरकार की नीतियों के खिलाफ लिखने,बोलने और प्रस्तुत करने के आरोप मे आजादी के कई मतवाले काल कोवरी मे कैद कर दिए गए। बापू अपने विचारों को व्यक्त करने से पीछे नहीं हटते थे। वे कहते भी की बिना अभिव्यक्ति के आजादी निर्थक है। उन्होंने साप्ताहिक अखबार यंग इंडिया मे अंग्रेजी सरकार की नीतियों की आलोचना की। नतीजा यह हुआ की बिरिटिश पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया और बाद मे अदालत ने उन्हे लोगों को सत्ता के खिलाफ भड़काने के आरोप मे छह साल की कैद की सजा सुना दी।यह पहली बार नहीं था। इसके पहले 1891 अंग्रेजों ने बंगबासी अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया था। उन्होंने एज आफ कॉन्स्टेंट बिल का विरोध किया था। 1908 मे बालगंगाधर तिलक ने चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा देने पर अंग्रेज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए निंदा की थी,नतीजा उन्हे देशद्रोही बताया गया था। इसी प्रकार 1921 मे स्वर्ण मंदिर के मामलों में अंग्रेजों के बढ़ते हस्तक्षेप के खिलाफ राजनेता और धार्मिक संगठन के प्रमुख मास्टर तारा सिंह के भाषण को राजद्रोह माना गया था।

देश का संविधान लिखा जा रहा था तब इस कानून पर खूब बहस हुई। यह कहा गया की धारा 124 औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है और एक लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। यह वाक् और अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटीकृत स्वतंत्रता के वैध अभ्यास में एक अवरोध है। फिर भी इस कानून को हटाने पर

राकेश दुबे
भारत जैसे विकासशील देश में भी अब मोबाइल फ़ोन और टेलीविजन अमीरी की निशानी न होकर आवश्यक उपकरण हो गये है।दुर्भाग्य से सरकार का इन उपकरणों और इनमें प्रयुक्त होने वाले पुर्जों की कीमतों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।ये दोनों उपकरण इनमें इस्तेमाल होने वाले ओपन सेल की कीमतें चढ़ने से विनिर्माता अब अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने लगे हैं। लैपटॉप और स्मार्टफोन की कीमतों में इजाफा हो सकता है। टीवी बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि ओपन सेल के दाम औसतन 15 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

मोबाइल फोन और टीवी में ओपन सेल प्रमुख पुर्जा होता है औरइन उपकरणो की कुल लागत में इसकी हिस्सेदारी 60 से 65 प्रतिशत होती है।मोबाइल फोन में भी इसका उपयोग होता है, और फोन की लागत में इसकी हिस्सेदारी टीवी के मुकाबले कम होती है।महंगे फोन में मार्जिन ज्यादा होता है, जिससे

विश्व साइकिल दिवस: साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा

योग गुरु महेश अग्रवाल
विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर कहा कि आज हम सब संकल्प लें की ज्यादा से ज्यादा साइकिल चलाने का प्रयास करेंगे, दुनियाभर में आज यानी 03 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जा रहा है। डेली लाइफ में साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व भर में साइकिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर है। इसके साथ-साथ ये इको फ्रेंडली है। साइकिल से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है। ये आपके देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी सही है। साइकिल चलाने के कई फायदे हैं, ये बाकी साधनों के मुकाबले सस्ती है, विश्वसनीय है, ये स्वच्छ और पर्यावरण के लिए अनुकूल परिवहन है।

असल में साइकिल चलाना एक व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस सुनिश्चित करता है। यह अधिक टिकाऊ है। इसके अलावा दो शताब्दियों से अधिक समय से लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यह वयस्कों और बच्चों दोनों के लिए उपयोगी है। साइकिल समावेशिता को भी बढ़ावा देती है क्योंकि यह बहुत महंगा नहीं है और समाज के अमीर और गरीब दोनों लोगों द्वारा वहन किया जा सकता है।साइकिलिंग कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है क्योंकि इसमें आंतरिक शून्य-उत्सर्जन मूल्य होता है। साइकिल चलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है,साइकिल चलाने से हृदय की फिटनेस, मांसपेशियों की ताकत और लचीलेपन में वृद्धि होती है। यह जोड़ों की गतिशीलता में सुधार करता है और तनाव को कम करने में मदद करता है।साइकिल चलाने से पैसे की बचत होती है, ये बहुत ही सस्ता होता है और इसको चलाने के लिए किसी लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होती है। स्थानीय पर्यावरण साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है।

साइकिल को हम जिंदगी का सबसे पहला

सर्वसम्मत नहीं बन पाई। फिर अदालत ने इस पर संज्ञान लिया। 1950 के दशक में दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों ने धारा 124ए को स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया था। एस.जी. वोम्बटकरे बनाम भारत संघ मामले में में दिये गए एक संक्षिप्त आदेश में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से निर्लांबत



कर दिया। लेकिन 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इन फैसलों को उलट दिया। न्यायालय ने पाया कि धारा 124ए लोक व्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में बचाव-योग्य है।

देशद्रोह को अपराध घोषित करने वाले इस प्रावधान का इस्तेमाल आज़ादी के बाद के क्रमिक शासनों द्वारा लोकतांत्रिक असंतोष के दमन के लिये किया गया है। लोकतान्त्रिक और आजाद भारत मे देशद्रोहिता के आरोप मे जो मुकदमे दर्ज किए गए,वे भी बड़े दिलचस्प है। पाटीदार आंदोलन को हवा देने वाले हार्दिक पटेल राजद्रोह के जिम्मेदार ठहराएं गए तो 2003 में राज्य सरकार के खिलाफ भाषण देने पर राजस्थान सरकार ने विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर लिया। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करने और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर सांसद नवनीत राणा व विधायक पति रवि राणा के खिलाफ

मोबाइल फ़ोन और टेलीविजन की बढ़ती कीमतें

कंपनियां लागत में बढ़ोतरी का बोझ सह सकती हैं।पिछले साल 2022 ओपन सेल के दाम कम थे, लेकिन 2023 की शुरुआत से इसमें तेजी देखी जा रही है। जनवरी से अब तक इसके दाम 15 से 17 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं।

32 इंच के टीवी में इस्तेमाल होने वाला ओपन सेल करीब 27 डॉलर प्रति पैनल का पड़ता है। जो कम्पनी ठेके पर टीवी बनाती है। उसने तो बढ़ी हुई लागत का पूरा भार अपने ग्राहकों पर डाल दिया है। सरकार चुप है चीन में 4 से 5 पैनल विनिर्माताओं के बीच गठजोड़ के कारण यह कीमतें बढ़ी हैं।

कोडक ब्रांड की लाइसेंसि कंपनी सुपर प्लास्टॉनिक्स भी जून से टीवी के दाम 10 ?प्रतिशत बढ़ा रही है। टीवी और मोबाइल फ़ोन निर्माताओं का कहना है कि , ‘ पैनल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब तक इसकी कीमत 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है। इसके अलावा आपूर्ति की भी किश्त है। इसलिए निर्माता जून से अपने ब्रांड के टेलीविजन 10

एडवेंचर कह सकते हैं। गिरते-पड़ते हम साइकिल चलाना सीखते हैं।

उम्र के अनुसार साइकिल का भी अलग – अलग महत्व है। बचपन में साइकिल शौकिया तौर पर चलाते हैं, फिर धीरे – धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं, तो कई लोग साइकिल से अपने काम पर जाते हैं। लेकिन वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी बदल गई और महत्व भी बदल गया है। एक वक्त था जब साइकिल को परिवार में साधन का हिस्सा माना



जाता था लेकिन अब यह सिर्फ एक्सरसाइज के तौर पर प्रयोग की जाती है। साइकिल का दौर 1960 से लेकर 1990 तक काफी अच्छा चला है। इसके बाद समय परिवर्तित होता गया। आज एक्सरसाइज के साथ ही साइकिल का उपयोग एक एथलेटिक्स द्वारा भी किया जाता है। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है। इसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण दूषि से सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, इम्युनिटी भी बढ़ती है।रोज साइकिल चलाने से फैट जल्दी कम होता है, बाँडी फिट रहती है। करीब 30 मिनट रोज साइकिल

राज्य सरकार ने इसी धारा के तहत केस दर्ज किया था। तमिलनाडु के कुंडकुलम में एक गाँव पर इसलिये देशद्रोह कानून थोप दिया गया था, क्योंकि वे वहाँ परमाणु संयंत्र बनाए जाने के पक्ष में नहीं थे। इतना ही नहीं,2014 में झारखंड में तो विस्थापन का विरोध कर रहे आदिवासियों पर भी देशद्रोह कानून चलाया गया था।

देश मे राजद्रोह कानून की वर्तमान में स्थिति यह है की यह भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए के तहत राजद्रोह एक अपराध है। यह कानून राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करता है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति मौखिक,लिखित,संकेतों या दृश्य रूप में घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है। विद्रोह में वैमनस्य और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल होती हैं। हालाँकि इस खंड के तहत घृणा या अवमानना फैलाने की कोशिश किये बिना की गई टिप्पणियों को अपराध की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। राजद्रोह गैर-जमानती अपराध है। राजद्रोह के अपराध में तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त करने से रोका जा सकता है। आरोपित व्यक्ति को पासपोर्ट के बिना रहना होता है,साथ ही आवश्यकता पड़ने पर उसे न्यायालय में पेश होना जरूरी है। दो साल पहले यह कानून तब फिर चर्चा में आया जब सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी,जिसमें देशद्रोह कानून पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। न्यायालय ने कहा,सरकार के प्रति असंतोष की असंवैधानिक रूप से अस्पष्ट परिभाषाओं के आधार पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अपराधीकरण करने वाला कोई भी कानून भारतीय संविधान मे उल्लेखित अभिव्यक्ति की

प्रतिशत तक महंगे कर रहे हैं । कीमतों में यह औसत वृद्धि 15प्रतिशत तक होने के आसार दिख रहे हैं। इन कम्पनियों को 43 इंच से बड़े स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री अधिक होने की उम्मीद है, जिससे कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन तक कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार हैं क्योंकि ओपन सेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

यह सही है ग्राहकों को कीमतों में वृद्धि का झटका तत्काल नहीं लगेगा क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के पास 30 से 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है।इस क्षेत्र में काम करने वाले छोटे दुकानदार साफ़ कह रहे हैं , ‘ कीमत बढ़ोतरी का असर अगले एक या दो महीनों में दिखने लगेगा।’ कारण पैनल (ओपन सेल) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं मगर बाजार में टीवी की कीमतें अभी नहीं बढ़ी हैं और बाज़ार प्रतीक्षा में है।इस बात की पूरी सम्भावना है कि ‘कंपनियां निकट भविष्य में कीमतें बढ़ाकर पुर्जों की कीमतों में तेजी के कारण बढ़ी हुई

मोबाइल और टेलीविजन की बढ़ती कीमतें

प्रतिशत तक महंगे कर रहे हैं । कीमतों में यह औसत वृद्धि 15प्रतिशत तक होने के आसार दिख रहे हैं। इन कम्पनियों को 43 इंच से बड़े स्क्रीन वाले टीवी की बिक्री अधिक होने की उम्मीद है, जिससे कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारी सीजन तक कीमतों में तेजी जारी रहने के आसार हैं क्योंकि ओपन सेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

यह सही है ग्राहकों को कीमतों में वृद्धि का झटका तत्काल नहीं लगेगा क्योंकि खुदरा विक्रेताओं के पास 30 से 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है।इस क्षेत्र में काम करने वाले छोटे दुकानदार साफ़ कह रहे हैं , ‘ कीमत बढ़ोतरी का असर अगले एक या दो महीनों में दिखने लगेगा।’ कारण पैनल (ओपन सेल) के दाम लगातार बढ़ रहे हैं मगर बाजार में टीवी की कीमतें अभी नहीं बढ़ी हैं और बाज़ार प्रतीक्षा में है।इस बात की पूरी सम्भावना है कि ‘कंपनियां निकट भविष्य में कीमतें बढ़ाकर पुर्जों की कीमतों में तेजी के कारण बढ़ी हुई

लोग साइकिल की सवारी कर खुद को चुस्त और दुरस्त रख सकते हैं। साइकिल की सवारी मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करती है। इसमें अन्य व्यायामों की तरह ना चोटिल होने का डर है और ना ही इसे चलाने न में किसी विशेष तकनीकी ज्ञान की जानकारी की आवश्यकता है।रोज़ाना साइकिल चलाने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में वसा भी नहीं बनती। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों को साइकिल की सवारी पीछे छोड़ देती है। शोध में सामने आया है कि निरंतर साइकिल चलाने वालों

स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है और संवैधानिक रूप से अनुमेय भाषण पर द्रुतशीतन प्रभाव का कारण बनता है।

अब विधि आयोग ने इस विवादित क़ानून को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है. यहीं नहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया है की भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित रखने के लिए यह कानून जरूरी है। आयोग ने कहा है कि ये क़ानून हटाने के लिए सिर्फ़ ये वजह काफी नहीं है कि ये क़ानून औपनिवेशिक दौर का है। भारतीय लोकतंत्र मे आंतरिक सुरक्षा के लिए इस कानून को बनाएं रखने का अर्थ यह है की सत्ता के खिलाफ लिखने, बोलने या दृश्य फिल्म की प्रस्तुति पर राजद्रोह हो सकता है। आधुनिक लोकतंत्र मे यह विश्वास किया जाता है की संविचार की स्वतंत्रता का अधिकार,अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार और असंतोष का अधिकार को स्वस्थ और परिपक्व लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्थाओं के बाद ही लोकतंत्र में लोगों की सहभागिता बहेगी। इसके साथ ही समाज के लिये अप्रासंगिक विचारों को निकाल देना देश की शासन व्यवस्था का उतरदायित्व है। आजादी के बाद कई सरकारों बनी और प्छद्मद्य गई।लेकिन वे इसव कानून को समाप्त करने का साहस नहीं जुटा पाई। भारत मे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 प्रचलित है। यह कानून केंद्र या राज्य सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिक्ल किसी भी तरह से कार्य करने से रोकने के लिये उसे हिरासत में ले सकता है।इस सरकार किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करने से रोकने या समुदाय के लिये आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिये भी हिरासत में ले सकती है।

जाहिर है आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले कानूनों की मौजूदगी के बाद भी राजद्रोह के औपनिवेशिक कानून पर संशय चिंता का विषय है। अंग्रेजों को कानून मे सुधार करने के लिए बार बार मजबूर करने वाले आजादी के मतवालों ने राजद्रोहिता नहीं की होती तो वे शायद ही देशभक्त कहलाते। फिर लोकतान्त्रिक देश मे राजद्रोहिता को देशद्रोहिता से जोड़ना किसी अभिशाप से कम नहीं है।

मोबाइल और टेलीविजन की बढ़ती कीमतें

लागत का कुछ बोझ ग्राहकों के कंधों पर डाल सकती हैं। मगर उसका असर वैसा नहीं होगा जैसा पिछले साल दिखा था ।’

कहने को सरकार स्मार्टफोन और टीवी के पुर्जों के लिए आयात शुल्क घटाकर बढ़ी हुई लागत की कुछ हद तक भरपाई का प्रयास कर सकती है। सरकार ने इस साल के आरंभ में बजट पेश करते समय टीवी पैनल के ओपन सेल के कुछ हिस्सों पर बुनियादी आयात शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने की घोषणा की थी।

पुर्जों की कीमतों में आई और सम्भावित तेजी से स्मार्टफोन अथवा लैपटॉप की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका नहीं है। इंटरनैशनल डेटा कॉरपोरेशन (आईडीसी) के आंकड़ों के अनुसार 2022 के दौरान देश में स्मार्टफोन की आपूर्ति इससे पिछले साल के मुकाबले 10 प्रतिशत घटकर 14.4 करोड़ रह गई थी। ऐसा मुख्य तौर पर मुद्रास्फूर्ति में तेजी और पुर्जों के दाम बढ़ने के कारण हुआ था।

मोबाइल और टेलीविजन की बढ़ती कीमतें

मो मुधुमेह और हृदयाघात का खतरा अन्य लोगों से कम रहता है। यह सच है कि साइकिल को वक्त ने चुनौती दी है।

सड़क पर दौड़ती बसें, ट्रक, कार, महंगी मोटरसाइकिल साइकिल चलाने वाले को रफ्तार में कहीं पीछे छोड़ देती हैं। इस तेज़ रफ्तार के साथ चल रही जिंदगी में हर किसी को वक्त की कमी है।मनुष्य ने विकास के पीछे अंधी दौड़ लगायी हुई है। उसमें साइकिल के सफ़र में लगता ज्यादा समय मनुष्य को चुभने लगता है। पर कोरोना ने दिखा दिया है कि कैसे प्रकृति मनुष्य की रफ्तार को कभी भी रोक सकती है और वैसे भी मेट्रो स्टेशनों की भीड़, बसों की दमघोड़ भीड़ और असुरक्षित तेज दौड़ती साइकिल दूर एक साइकिल के सफ़र का सड़क पर तेज दौड़ते वाहनों से सुरक्षित बना सकता है। साइकिल सवारी के दौरान हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य करना चाहिए और इस विश्व साइकिल दिवस के दिन सरकार को बिना किसी देरी के साइकिल की सवारी को शान को सवारी बनाने पर गम्भीरता से विचार करना शुरू कर देना चाहिए।

(आदर्श योग आध्यात्मिक केंद्र स्वर्ण जयंती पार्क कोलार रोड़ भोपाल के संचालक योग गुरु महेश अग्रवाल कई वर्षो से नि:शुल्क योग प्रशिक्षण के द्वारा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सीख रहे हैं, वर्तमान में भी ऑनलाइन एवं प्रत्यक्ष माध्म से यह कम उनमवत कर रहा है। योग प्रशिक्षण के दौरान साधकों को साइकिल चलाने के अभ्यास करवाते हुए उसके अनेक प्रकार के फायदों के बारे में बताया जाता है एवं साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है।)

कार्डिएक केयर में तकनीकी प्रगति के साथ निदान और उपचार में काफी सुधार हुआ है : डॉ. मिलन चाग

अहमदाबाद, एजेंसी। हाल के वर्षों में, भारत में आबादी के बीच दिल की बीमारियों में खतरनाक वृद्धि हुई है, जहां कोरोनरी धमनी रोग जिसे इस्केमिक हृदय रोग के रूप में भी जाना जाता है, दूसरों के बीच सबसे प्रचलित हृदय रोग है। कोरोनरी धमनी हृदय को रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। सीएडी तब विकसित होता है जब धमनियों में पट्टिका का निर्माण होता है, जिससे रक्त प्रवाह कम हो जाता है और सांस की तकलीफ और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी में पाया गया है कि दुनिया की लगभग 1.72 प्रतिशत आबादी इस्केमिक हृदय रोग से प्रभावित है, जिसकी व्यापकता दर प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 1,655 है और वर्ष 2030[1] में यह प्रसार दर बढ़कर प्रति 1,00,000 लोगों पर 1,845 से अधिक होने की उम्मीद है।



एचडीएफसी बैंक ने मध्य भारत और महाराष्ट्र में मेगा कार लोन मेले का शुभारंभ किया

मुंबई, एजेंसी। एचडीएफसी बैंक, भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक ने आज मध्य भारत और महाराष्ट्र में एक मेगा कार लोन मेला शुरू करने की घोषणा की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में 650 से अधिक बैंक शाखाएं प्रमुख ऑटोमोबाइल ब्रांडों और कार डीलरशिप के साथ साझेदारी में 2 और 3 जून को कार लोन अभियान की मेजबानी की। कार डीलर अपने ऑटोमोबाइल मॉडल दिखाने के लिए एचडीएफसी बैंक की शाखाओं में मौजूद रहेंगे और ग्राहकों को वाहनों की टेस्ट ड्राइव लेने की सुविधा भी दी गई। बैंक पात्र ग्राहकों को ऑन-द-स्पॉट कार लोन की स्वीकृति प्रदान करेगा। एचडीएफसी बैंक सभी ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करता है। कार-लोन मेला की लक्ष्य ग्राहकों को ऑटोमोबाइल फाइनेंस तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए की गई है।

लाखों डेरी किसानों ने भारत को विश्व की डेरी बनाने का संकल्प लिया

नई दिल्ली, एजेंसी। विश्व दुध दिवस पर आज लाखों डेरी किसानों ने भारत को विश्व की डेरी बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि ग्रामीण भारत से गरीबी उन्मुक्त और सामाजिक-आर्थिक बदलाव भारत को वैश्विक डेरी क्षेत्र में अग्रणी बनाकर ही संभव हो सकता है। इस अवसर पर 22 दुध उत्पादक कंपनियों (सहकारिता के समान सिद्धांतों पर परिचालित किसान उत्पादक संगठन) ने हाथ से हाथ मिलाकर विश्व उत्पादन में भारत का हिस्सा बढ़ाकर भारत को विश्व की डेरी बनाने, देश के दूर-दराज के क्षेत्रों से भी दूध इकट्ठा कर उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध और दुध उत्पाद उपलब्ध कराने, दुध संचय की निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से किसान सदस्यों को प्रतिस्पर्धी मूल्य उनके बैंक खाते में देने और नस्ल उत्तिकरण और बेहतर पशु प्रबंधन से दुध उत्पादन में वृद्धि करने के संकल्प लिये।



अब होगा ‘कर्म या काण्डे’ का मुकाबला शुरू! एमटीवी रोडीज़- कर्म या काण्डे का हिम्मतोत से भरा रोमांचक सफर शुरू हुआ!

मुंबई, एजेंसी। कर्म तो बहुत हो गया ! अब है काण्डम की बारी ! एमटीवी रोडीज़- कर्म या काण्ड , बेमिसाल युथ एडवेंचर रियलिटी टेलीविजन शो का यह नया सीजन जबरदस्त अ एक्शन, हिम्मत और बिजली की फूतीं जैसे कॉम्प्लिशिन के साथ मनोरंजन को नई परिभाषा देने के लिये तैयार है ! जबरदस्ती दांव के साथ, इस मशहूर सफर में प्रतियोगी जीत के रास्ते पर चलते हुए भारी-भरकम चुनौतियों और आकस्मिक ट्विस्ट्स और टर्न्स से गुजरेंगे, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक रणभूमि से होकर काज़ा के पवित्र मैदानों तक जाएगी ! मेजबान सोनू सूद और गैंग लौडस्टे प्रिंस नरला, गीतम गुलाटी और रिया चक्रवर्ती देश को बेजोड़ मनोरंजन देने के लिये तैयार हैं ।

स्वस्थ भविष्य की थीम के साथ वेस्टीज मार्केटिंग ने पूरे किए अपने सफर के 19 साल

नई दिल्ली, एजेंसी। हेल्थ, वेलनेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की श्रेणी में विस्तृत पोर्टफोलियो के साथ भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में शुमार वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2004 में अपनी शुरुआत के बाद से 19 साल का सफर पूरा कर लिया है। हेल्थ के अपने मुख्य कारोबार को विस्तार देते हुए वेस्टीज ने स्वस्थ भविष्य (फ्यूचर हेल्दी) की थीम के साथ अपने सफर के दूसरे दशक में कदम रखा है। स्वास्थ्य इसका मुख्य कारोबार है, जो इसके उत्पादों, लोगों और साझेदारों समेत पूरे इकोसिस्टम को जोड़ता है। वेस्टीज मार्केटिंग लगातार वेलेनेस सेक्टर के विकास में योगदान दे रही है। हेल्थ एवं वेलनेस कैटेगरी में अपने श्रेष्ठ उत्पादों की रेंज के साथ वेस्टीज उपभोक्ताओं को स्वस्थ जीवनशैली प्रदान करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। वेस्टीज ने बेहतर कल के लिए पूरे भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स को हेल्थ एवं वेलनेस प्रोडक्ट्स तक पहुंच देते हुए उनकी जिंदगियों को सशक्त किया है।

अर्थव्यवस्था में तेजी: लगातार 14वें महीने 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी संग्रह, यह अब तक का सर्वाधिक स्तर

नई दिल्ली, एजेंसी। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बेहतरी जारी है। लगातार 14वें महीने संग्रह 1.40 लाख करोड़ रुपये के पार हुआ है। वहीं, साल 2017 से लेकर अब तक पांच बार जीएसटी संग्रह 1.50 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

वित्त मंत्रालय ने बुधस्तिवार को बताया कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी और चोरी रोकने का असर दिखा है। मई में जीएसटी संग्रह 1.57 लाख करोड़ रहा है। इससे पहले अब तक का रिकॉर्ड संग्रह अप्रैल, 2023 में रहा है जो 1.87 लाख करोड़ रुपये था।

आंकड़ों के मुताबिक, मार्च, 2023 में 1.60 लाख करोड़ रुपये, जनवरी में 1.57 लाख करोड़ रुपये, अक्तूबर में 1.51 लाख करोड़ रुपये, अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ और अप्रैल, 2022 में 1.67 लाख करोड़ रुपये का संग्रह मिला था। देश के जिन राज्यों में जीएसटी संग्रह मई में सबसे ज्यादा रहा है, उनमें महाराष्ट्र में 23,536 करोड़, कर्नाटक में



10,317 करोड़, गुजरात में 9,800 करोड़ और तमिलनाडु में 8,953 करोड़ रुपये हैं।

आरबीआई की बैठक से पहले बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई व पीएनबी के कर्ज हुए महंगे

नई दिल्ली, एजेंसी। इस महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले ही बैंकों ने कर्ज महंगा करना शुरू कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ इंडिया का एक जून से कर्ज महंगा हो जाएगा।

हालांकि, पीएनबी कुछ अवधि के लोन को सस्ता भी कर दिया है। पिछले साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने 2.5 प्रतिशत ब्याज दरें बढ़ाई हैं। आरबीआई की बैठक आगे हफ्ते से होनी है, जिसमें रेपो दर पर फैसला होना है। हालांकि, अप्रैल की बैठक में केंद्रीय बैंक ने इसे जस का तस रखा था।

आईसीआईसीआई बैंक- इसने 6 माह के कर्ज की दर बढ़ाकर 8.75 फीसदी कर दी है, जबकि एक साल वाले कर्ज की दर 8.85 फीसदी होगी।

पीएनबी- इसने सभी अवधि के कर्ज की दर में 0.10 फीसदी का इजाफा किया है। इसकी एक साल की दर 8.60 फीसदी और तीन साल के कर्ज की दर 8.90 फीसदी होगी।

बैंक ऑफ इंडिया- इस बैंक ने सभी अवधि के कर्ज की दर में 0.05 फीसदी का इजाफा किया है। एक साल की दर अब 8.65 फीसदी और 6 महीने की दर 8.45 फीसदी होगी।

कैसियो सिमोस बने टेट्रा पैक साउथ एशिया के प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली, एजेंसी। ग्रणी खाद्य प्रसंस्करण और पैकेजिंग समाधान कंपनी, टेट्रा पैक ने साउथ एशिया मार्केट के लिए कैसियो सिमोस को प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। सिमोस 1 जून, 2023 से नया पद संभालेंगे, वो आशुतोष मोनोहर का स्थान लेंगे, जो टेट्रा पैक में 20 साल के कार्यकाल सहित चार दशकों से अधिक के शानदार कॉर्पोरेट करियर के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

कैसियो के पास टेट्रा पैक में पिछले 20 वर्षों में विभिन्न व्यवसायों में विभिन्न भूमिका निभाने का समृद्ध अनुभव है। हाल ही में, वह टेट्रा पैक एंडीना के प्रबंध निदेशक थे। ग्रोथ के लिए कस्टमर्स इन्वोवेट में मदद करने के एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, उनकी विशेषज्ञता साउथ एशिया रीजन, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं, में कंपनी के विकास और विस्तार में



महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

आशुतोष ने कहा, विकास के इस अगले चरण में टेट्रा पैक साउथ एशिया का नेतृत्व करने के लिए कैसियो का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनका व्यापक अनुभव और नेतृत्व कौशल हमारे

सैमसंग ने न्यूरल क्राण्टम प्रोसेसर 4के के साथ लॉन्च किया मेड इन इंडिया ओलएईडी टीवी

सैमसंग ओएलईडी डिलीवर करता है गहरे

काले, साफ सफेद और जीवंत रंग

गुरुग्राम, एजेंसी। पिछले 17 वर्षों से लगातार दुनिया के नंबर एक टीवी ब्रांड सैमसंग ने आज न्यूरल क्राण्टम प्रोसेसर 4के के साथ अपनी ओलएईडी टीवी रेंज को भारत में लॉन्च करने की घोषणा की जो गहरे काले, साफ सफेद और जीवंत रंग डिलीवर करती है। सैमसंग ओलएईडी टीवी रेंज के सभी मॉडल भारत में ही तैयार किए जाएंगे। सैमसंग की ओलएईडी टीवी रेंज में दो सीरीज होंगे- एस95सी और एस95सी। दोनों ही सीरीज तीन आकारों 77-इंच, 65-इंच और 55-इंच में आ रहे हैं, जिनकी शुरुआत 169,990 रुपये से है। ओलएईडी टीवी की यह रेंज आज से भारत के सभी प्रमुख रिटेल स्टोर, और ऑनलाइन सैमसंग.कॉम पर उपलब्ध होगी। सैमसंग इंडिया के कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहनदीप सिंह ने कहा, हम ओलएईडी टीवी की हमारी नई रेंज के साथ इनोवेशन की सीमाओं का और विस्तार कर रहे हैं। हमने बेजोड़ पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करने के लिए न्यूरल क्राण्टम प्रोसेसर 4के और ओएलईडी जल रही है। प्लिपकार्ट को एक साथ जोड़ दिया है और इससे ओलएईडी टीवी और बेहतर हो गया है।

फ्लिपकार्ट की बिग एंड ऑफसीजन सेल शुरू करने की घोषणा

फ्लिपकार्ट की बिग एंड ऑफसीजन सेल के बहाने फैशन और लाइफस्टाइल कैटेगरी का अब तक का सबसे बड़ा उत्सव

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत की स्वदेशी ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस फ्लिपकार्ट ने अपनी बहुप्रतीक्षित बिग एंड ऑफसीजन सेल शुरू करने की घोषणा की, जिससे करीब 2,00,000 विक्रेताओं और 10,000 से ज्यादा ब्रैंड एक साथ आएंगे, ताकि देश भर के लाखों ग्राहकों को फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल से जुड़े उत्पादों की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराई जा सके। 1 जून, 2023 से शुरू होने वाले और एक सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान ग्राहकों को खरीदारी का अलग तरह का खरीदारी का अनुभव मिलेगा। इसके लिए इमेज सर्च, वीडियो कैटलॉग, वर्चुअल ट्राई-ऑन, वीडियो कॉमर्स और टॉप फ्लिर्ट्स जैसे टेक्नोलॉजी आधारित प्रयासों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा, प्लिपकार्ट को अपने डिजिटल फ्ल्ट ब्रैंड्स को लेकर लोगों की बढ़ती दिलचस्पी देखने को मिल रही है। ऑनलाइन फैशन कैटेगरी को पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्लिपकार्ट को अकेले समग्र सीजन सेल के दौरान इस कैटेगरी में लाखों ऑर्डर



मिले हैं जिससे फैशन के प्रति लोगों की दिलचस्पी का पता चलता है। आज के समय में फैशन कैटेगरी प्लिपकार्ट की वृद्धि को गति देने वाले प्रमुख कारकों में से एक बन गई है, क्योंकि 40 फीसदी से ज्यादा नए

ग्राहक इसी कैटेगरी के माध्यम से आ रहे हैं। इस आयोजन के बारे में अभिषेक मालू, सीनियर डायरेक्टर, प्लिपकार्ट फैशन ने कहा, प्लिपकार्ट में एंड ऑफसीजन सेल हमारे लिए सही मायनों में एक त्योहार की तरह है और यह हमारे हमारे इकोसिस्टम के सभी पक्षों के लिए खुशी का मौका होता है। एक के बाद एक हर सीजन में इस आयोजन को पूरे भारत के ग्राहकों से काफी सराहना मिली है जिससे हमारे मार्केटप्लेस पर विक्रेताओं और ब्रैंड्स को जबरदस्त वृद्धि करने का मौका मिला है। हमारी लगातार कोशिश टेक्नोलॉजी आधारित खरीदारी का आसान अनुभव उपलब्ध कराकर नए फैशन परिधानों, फुटवियर और एक्सेसरीज की व्यापक रेंज लोगों तक पहुंचाना है। श्रेणी के लिहाज से सर्वश्रेष्ठ लॉन्च के अलावा, स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध इंटरफेस से हमारी वृद्धि को गति मिलती है और हमने यह पाया है कि देशभर के ग्राहक स्थानीय भाषा में उपलब्ध हमारे इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए ब्राउजिंग करने में ज्यादा समय बिता रहे हैं।

बैंकों में लावारिस पड़े हैं हजारों करोड़ रुपए, आरबीआई ने शुरू किया 100 डेज 100 पे अभियान

नई दिल्ली, एजेंसी। देश के बैंकों में लावारिस पड़े हजारों करोड़ रुपए की जानकारी हासिल करने और उनके निपटारे के लिए रिजर्व बैंक ने शुक्रवार से 100 दिन 100 पे का अभियान का शुरू किया है। आरबीआई यह अभियान बैंकिंग प्रणाली में लावारिस जमा की मात्रा को कम करने और ऐसी जमा राशि को उनके सही मालिकों/दावेदारों को वापस करने के लिए कर रहा है। आरबीआई के इस अभियान के तहत 100 दिनों के अंदर भारत के हर एक जिले में हर एक बैंक में जमा 100 अनक्लेमेट डिपॉजिट रकम का पता लगाकर उनका निपटारा किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने अपने इस अभियान के बारे में कहा कि इस तरह से बैंकिंग सिस्टम में जमा लावारिस रकम की मात्रा को कम किया जा सकेगा और डिपॉजिट को उनके सही मालिकों और दावेदारों तक पहुंचाया जा सकेगा।

कितना है अनक्लेमेट डिपॉजिट

अनक्लेमेट डिपॉजिट उन्हे कहा जाता है, जिसे 10 साल या उससे भी अधिक समय से किसी तरह का ट्रान्जेक्शन नहीं किया गया हो। बैंकिंग सिस्टम

में इसे इनएक्टिव डिपॉजिट माना जाता है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने फरवरी, 2023 तक बिना दावे वाली करीब 35,000 करोड़ रुपए की राशि रिजर्व बैंक को ट्रांसफर की थी, यह राशि उन खातों में जमा थी जिनमें 10 साल या उससे अधिक समय से कोई लेन-देन नहीं हुआ। ये रकम अलग-अलग बैंकों के 10.24 करोड़ खातों से संबंधित थी। आरबीआई ने कहा कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जब किसी डिपॉजिटर के मृत्यु के बाद उनके नामित/कानूनी उत्तराधिकारी संबंधित बैंक (बैंकों) पर दावा करने के लिए आगे नहीं आते हैं।

वर्तमान में, देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास लावारिस जमा राशि सबसे ज्यादा है। एसबीआई के पास 8,086 करोड़ रुपए की लावारिस जमा राशि है। दूसरे नंबर पर पंजाब नेशनल बैंक है जिसके पास 5,340 करोड़ रुपए का लावारिस जमा है। इसके बाद केनरा बैंक 4,558 करोड़ रुपए और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है, जिसके पास 3,904 करोड़ रुपए का लावारिस जमा है।

अधिक है। कंपनी ने बताया, धरेलू बाजार में बिक्री 13 फीसदी बढ़कर 1.51 लाख रही। यात्री वाहनों की बिक्री 15 फीसदी बढ़ी। छोटी कारों की बिक्री हालांकि 30 फीसदी गिर कर 12,236 इकाई रही। कापैक्ट कारों में 5 फीसदी का इजाफा रहा। कंपनी का नियात 3 फीसदी गिरकर 26,477 इकाई रहा।

बजाज ऑटो -मई में 29 फीसदी बढ़कर 3.55 लाख इकाई रही जो एक साल पहले 2.76 लाख रही थी। दोपहिया वाहनों की बिक्री 3.08 लाख रही जो एक साल पहले 2.50 लाख थी। नियात 1.53 लाख से घटकर 1.13 लाख पर रहा। वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 80 फीसदी बढ़ी।

टाटा मोटर्स - बिक्री 2 फीसदी गिरकर 74,973 इकाई रही। यात्री ईवी की बिक्री 3,505 से 66 फीसदी बढ़कर 5,805 रही। वाणिज्यिक बिक्री में 12 फीसदी घटी है।

बिजली खपत बढ़ी- मई में बिजली खपत 1.04 फीसदी बढ़कर 136.56 अरब यूनिट पर पहुंच गई है।

यूपीआई ने बनाया नया रिकॉर्ड, मई में 14.3 लाख करोड़ रुपये का हुआ लेनदेन



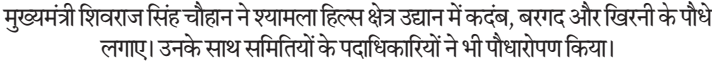
नई दिल्ली, एजेंसी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेनदेन ने मई में मूल्य के मामले में 14.3 लाख करोड़ रुपये और वॉल्यूम के मामले में 9.41 अरब का नया रिकॉर्ड हासिल किया है। यह अप्रैल की तुलना में मूल्य में 2 प्रतिशत (14.07 लाख करोड़) व वॉल्यूम में 6 प्रतिशत (8.89 अरब) की बढ़ोतरी है।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के मुताबिक, मई के आखिरी दस दिनों में करीब 3.96 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ। 2022-23 में मई की तुलना में लेनदेन की मात्रा में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मूल्य में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आईएमपीएस से लेनदेन अप्रैल में 5.21 लाख करोड़ की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत बढ़कर 5.26 लाख करोड़ हो गया। फास्टेज लेनदेन के वॉल्यूम में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अप्रैल में यह 30.5 करोड़ से मई में 33.5 करोड़ पहुंच गई। मई में 6 प्रतिशत बढ़कर 5,437 करोड़ रुपये हो गया।

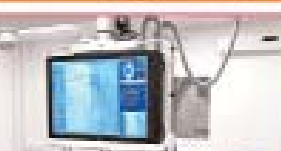
तीसरी औद्योगिक नीति के लिए विचार-विमर्श जारी- सरकार नई औद्योगिक नीति बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी विचार-विमर्श कर रही

किसानों से केंद्र सरकार ने

अब तक खरीदे 262 लाख टन गेहूं- केंद्र सरकार ने किसानों से इस साल अब तक 262 लाख टन गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की है। इसके एवज में किसानों को 47,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। सरकार ने चालू सीजन में 341.5 लाख टन खरीद का लक्ष्य रखा है। मंत्रालय के मुताबिक, रबी सीजन की गेहूं खरीद आगे भी जारी रहेगी। 30 मई तक जो खरीद हुई है, वह पिछले साल की 188 लाख टन खरीद से 74 लाख टन ज्यादा है। इससे 21.27 लाख किसानों को अच्छा फायदा हुआ है। खरीद में सबसे अधिक योगदान पंजाब का रहा है। यहां से 121.27 लाख टन, मध्यप्रदेश से 70.98 लाख टन और हरियाणा से 63.17 लाख टन गेहूं खरीदा गया है।



छिन्दवाड़ा का एकमात्र हार्ट केयर हॉस्पिटल



हार्ट अटैक का संपूर्ण उपचार, एन्जियोप्लास्टी, एन्जियोप्लास्टी
सभी हृदय रोगों के उपचार की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध

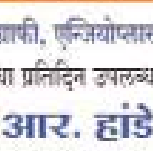
डॉ. प्रियदर्शन आर. हांडे
M.D., D.M., Cardiologist (Nagpur)

प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को उपलब्ध रहेंगे

2D-ECHO & ECG जीव एवं ओ.पी.डी. समय- प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक

एन्जियोप्लास्टी एवं एन्जियोप्लास्टी
मात्र 65000/- रु. में

मंगलवार
शुक्रवार
रविवार



जानकारी/अपडेटेड हेतु सम्पर्क करें :-

आरोग्य हेल्थकेयर
मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल

सिटी प्राइड बिल्डिंग, पूजा होटल के आगे, परासिया रोड, छिन्दवाड़ा (म. प्र.) www.aarogyahospitals.org

 **07162-242242, 6262640425, 6262640426**
9691938897, 9425845755, 9039268309